

तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

प्रलिस के लयः

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, रक्षा अधगिरहण प्रकरया 2020, रक्षा क्षेत्र से संबंधतः पहल ।

मेन्स के लयः

रक्षा और संबंधतः चुनौतयों के लयः स्वदेशीकरण का महत्त्व ।

चर्चा में कयों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा वनरिमाण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लयः तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के एक भाग के रूप में 351 प्रणालयों और घटकों के आयात को प्रतबिंधतः कर दया है ।

- जून 2021 में MoD ने दूसरी नकारात्मक आयात सूची को 108 वस्तुओं की 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' के रूप में नामतः कया था ।
- 101 वस्तुओं वाली 'प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण' (First Negative Indigenisation) सूची को अगस्त 2020 में अधसूचितः कया गया था ।

प्रमुख बडुः

- वसूली:**
 - सभी 351 वस्तुओं को अब [रक्षा अधगिरहण प्रकरया \(डीएपी\) 2020](#) में दया गए प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा ।
 - डीएपी 2020 में नमिनलखतः खरीदारी से संबंधतः श्रेणयों - खरीद (भारतीय स्वदेशी रूप से वकिसतः और नरमितः), खरीद (भारतीय), खरीद और बनाना (भारतीय), खरीद (भारत में वैश्वकः नरिमाण) और खरीद (वैश्वकः) शामिल हैं ।
- समय-सीमा:**
 - दसंबर 2022 से 172 प्रणालयों और घटकों के आयात को रोक दया जाएगा, जबकः 89 वस्तुओं के एक अन्य बैच पर प्रतबिंध दसंबर 2023 से लागू होगा । तथा 90 वस्तुओं का आयात दसंबर 2024 से रोक दया जाएगा ।
- शामलः वस्तुएँ:**
 - इस सूची में सेंसर, समियुलेटर, हथयार और गोला-बारूद जैसे- हेलीकॉप्टर, नेकस्ट जेनरेशन कॉरवेट, एयरबोर्न अरली वार्नगः एंड कंट्रोल (AEW&C) ससि्टम, टैंक इंजन, **मीडयःम रेंज सरफेस टू एयर मसःइल (MRSAM)** आदः को शामिल कया गया है ।
- महत्त्व:**
 - यह आत्मनरिभर पहल हर वर्ष लगभग **3,000 करोड रुपए के बराबर वदःशी मुद्रा की बचत** करेगी ।
 - यह आत्मनरिभरता [आत्मनरिभर भारत](#) की स्थतःतः प्राप्त करने और रक्षा नरियात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लयः सार्वजनकः तथा नजी क्षेत्र की सकरयः भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगी ।
 - यह सूची न केवल स्थानीय रक्षा उद्योग की क्षमता को महत्त्व देती है, बल्कः प्रौद्योगकःी और वनरिमाण क्षमताओं में नए नवःश को आकर्षतः करके **घरेलू अनुसंधान तथा वकःस** को भी गतः प्रादान करेगी ।
 - यह सूची 'स्टार्ट-अप' के लयः एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रादान करती है, कयोंकः इस पहल से **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को अत्यधकः बढ़ावा मलैगा ।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण

- परचयः**
 - स्वदेशीकरण आत्मनरिभरता प्राप्त करने और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लयः देश के भीतर कसःी भी **रक्षा उपकरण के वकःस और उत्पादन की क्षमता** है ।
 - रक्षा उत्पादन में आत्मनरिभरता रक्षा उत्पादन वभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है ।
 - रक्षा अनुसंधान वकःस संगठन (डीआरडीओ), रक्षा सार्वजनकः क्षेत्र के उपकरण (डीपीएसयु)** और नजी संगठन रक्षा

उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभा रहे हैं।

- भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है और अगले पाँच वर्षों में सशस्त्र बलों द्वारा रक्षा खरीद पर लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है।

■ भूमिका:

- सोवियत संघ पर अत्यधिक निर्भरता के कारण रक्षा औद्योगीकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में बदलाव लाया।
- वर्ष 1980 के दशक के मध्य से सरकार ने अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) में संसाधनों का इस्तेमाल किया ताकि डीआरडीओ को हाई प्रोफाइल परियोजनाएँ शुरू करने हेतु संकषम बनाया जा सके।
- रक्षा स्वदेशीकरण में एक महत्त्वपूर्ण शुरुआत वर्ष 1983 में हुई थी जब सरकार ने 5 मसिाइल सिसिम (पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग) विकसित करने के लिये एकीकृत नरिदेशति मसिाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) को मंजूरी दी थी।
- सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वदेशी प्रयास पर्याप्त नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी में सह-विकास और सह-उत्पादन की ओर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी, जब भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मसिाइल का उत्पादन करने के लिये एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

■ आवश्यकता:

◦ राजकोषीय घाटा कम करना:

- भारत दुनिया में (सऊदी अरब के बाद) दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है।
- उच्च आयात निर्भरता से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है।

- दुनिया में पाँचवाँ सबसे बड़ा रक्षा बजट होने के बावजूद, भारत अपने हथियार प्रणालियों का 60% विदेशी बाजारों से खरीदता है।

◦ सुरक्षा दृष्टिकोण:

- रक्षा में स्वदेशीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। यह तकनीकी विशेषज्ञता को बरकरार रखता है और स्पनि-ऑफ प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है जो अक्सर इससे उत्पन्न होते हैं।
- उरी, पठानकोट और पुलवामा हमलों जैसे लगातार संघर्ष वरिष्ठ उल्लंघन से जुड़े खतरों से बचने के लिये स्वदेशीकरण की आवश्यकता है।

◦ रोजगार सृजन:

- इससे उपग्रह उद्योगों का निर्माण होगा जो बदले में रोजगार के अवसरों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- सरकारी अनुमानों के अनुसार, रक्षा संबंधी आयातों में 20-25% की कमी से भारत में सीधे तौर पर अतिरिक्त 100,000 से 120,000 अत्यधिक कुशल रोजगार सृजन हो सकता है।

◦ सामरिक क्षमता:

- एक आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग भारत को शीर्ष वैश्विक शक्तियों में स्थान प्रदान करेगा।

◦ देशभक्ति की धारणा:

- राष्ट्रीयता और देशभक्ति रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से बढ़ सकती है, जो बदले में न केवल भारतीय बलों के विश्वास को बढ़ावा देगी बल्कि उनमें अखंडता और संप्रभुता की भावना को भी मजबूत करेगी।

■ चुनौतियाँ:

- रक्षा के स्वदेशीकरण के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिये एक संस्थागत क्षमता का अभाव।
- बुनियादी ढाँचे की कमी से भारत की रसद लागत बढ़ जाती है जिससे देश की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता कम हो जाती है।
- भूमि अधिग्रहण के मुद्दे रक्षा निर्माण और उत्पादन में नए प्लेयर्स के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हैं।
- **DPP** (रक्षा खरीद नीति, जिसे अब DAP 2020 से बदल दिया गया है) के तहत नीतितंत्र दुविधा ऑफसेट आवश्यकताओं के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद नहीं मिली। (ऑफसेट एक विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंधित मूल्य का एक हिस्सा है जिसे भारतीय रक्षा क्षेत्र में फरि से निवेश किया जाना चाहिये, या जिसके खिलाफ सरकार प्रौद्योगिकी खरीद सकती है)।
 - केवल सरकार-से-सरकारी समझौते (G2G), एकल विक्रेता अनुबंध या अंतर-सरकारी समझौते (IGA) में अब ऑफसेट क्लॉज नहीं होंगे।
 - DAP 2020 के अनुसार, अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय सौदे जो प्रतिस्पर्धी हैं और इसके लिये कई विक्रेता हैं, उनके पास 30% ऑफसेट क्लॉज जारी रहेगा।

■ संबंधित पहलें:

◦ FDI सीमा में वृद्धि:

- मई 2020 में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रतिस्पर्धी विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था।

◦ आयुध निर्माणी बोर्डों का नगिमीकरण:

- अक्टूबर 2021 में, सरकार ने चार दशक पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को भंग कर दिया और युद्ध सामग्री से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण के लिये सात नई राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों के तहत 41 कारखानों को मिला दिया।

◦ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज:

- DISC का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रोटोटाइप बनाने और/या उत्पादों/समाधानों का व्यावसायीकरण करने के लिये स्टार्टअप/एमएसएमई/इनोवेटर्स का समर्थन करना है।
- इसे रक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मशिन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है।

◦ सृजन पोर्टल:

- यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिये उपकरण लेने की सुविधा प्रदान करता है।

◦ ई-बिजि पोर्टल:

- ई-बजि पोर्टल पर औद्योगिक लाइसेंस (IL) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है।

आगे की राह

- सभी आपत्तियों और विवादों से निपटने के लिये एक स्थायी मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना की जा सकती है।
- नज्दी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक है क्योंकि यह कुशल और प्रभावी प्रौद्योगिकी तथा स्वदेशी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक मानव पूंजी का संचार कर सकता है।
- सॉफ्टवेयर उद्योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों का उपयोग स्वदेशी रूप से "चपि" के विकास और निर्माण के लिये किया जाना चाहिये।
- DRDO का विश्वास और अधिकार बढ़ाने के लिये उसे वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना।
- रक्षा उत्पादन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और नरंतरता सुनिश्चित करने के लिये लंबे कार्यकाल दिये जाने की आवश्यकता है।
- तीनों सेवाओं के बीच इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता में सुधार किया जाना चाहिये, नौसेना ने स्वदेशीकरण के पथ पर अच्छी तरह से प्रगति की है, मुख्य रूप से इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता, नौसेना डिज़ाइन ब्यूरो के कारण।
- एक रक्षा निर्माता के लिये मज़बूत आपूर्ति शृंखला महत्त्वपूर्ण है जो लागत को अनुकूलित करना चाहती है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/third-positive-indigenisation-list>

